भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3365
गुरुवार 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कार्बन उत्सर्जन में कमी

3365. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी:
क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु सहित देश भर में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विमानपत्तनों पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए कोई राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन और कार्बन-तटस्थ विमानपत्तन प्रचालनों को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने हरित विमानन अवसंरचना के संबंध में कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या प्रायोगिक परियोजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों और आगामी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकासकर्ताओं को कार्बन तटस्थता और नेट जीरो की स्थिति प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का परामर्श दिया है। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय ने सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास प्रस्ताव, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), आदि में डिजाइन / मानकों को शामिल करके आरंभिक स्तर पर ही कार्बन उत्सर्जन में कमी के उपायों और नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की सलाह दी है।

नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) स्रोत हवाईअड्डों पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायता करते हैं। तदनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) सहित हवाईअड्डा प्रचालकों ने हरित और नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और स्व-उपभोग के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। कुछ हवाईअड्डे ओपन एक्सेस के माध्यम से भी हरित ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। अब तक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 94 हवाईअड्डों सहित 100 हवाईअड्डों ने 100% हरित ऊर्जा उपयोग आरंभ कर लिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए भी उपाय किए हैं। इसके अलावा, 72 एएआई हवाईअड्डों पर 18 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की संचयी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) शुरू किए गए हैं।

हवाईअड्डे एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन (एसीए) कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जो हवाईअड्डों के लिए एक स्वैच्छिक वैश्विक कार्बन प्रबंधन मानक

है। इसके तहत, (04) हवाईअड्डों नामतः दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद ने प्रत्यायन का उच्चतम स्तर 5 प्राप्त कर लिया है और ये हवाईअड्डें कार्बन न्यूट्रल बन गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) ने अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बाजार आधारित उपाय अर्थात कार्बन ऑफसेटिंग रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (कोर्सिया) को अपनाया है और इस संगठन का सदस्य राष्ट्र होने के नाते, भारत के लिए वर्ष 2027 से अनिवार्य चरण का अनुपालन करना अपेक्षित है। भारत संधारणीय विमानन ईंधन के लिए आईसीएओ की सहायता, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (एसीटी-एसएएफ) कार्यक्रम में भी शामिल हो गया है और विमानन क्षेत्र के लिए वैश्विक पर्यावरण मानकों के विकास हेतु विमानन पर्यावरण संरक्षण समिति (सीएईपी) कार्य समूहों में भाग लेता है।

******